MR. SPEAKER : I have followed the rules more than the hon. Member.

12.25 hrs.

श्री कंवरलाल गुप्त : मंत्री महोदय के लिए अच्छा होगा वह सारे सदन् की भावनाओं की क़द्र करें और इस को मान लें। यह न हो कि जब इस के लिए जन आन्दोलन हो तब इस को वह मानें।

मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार वह जो पत्र नहीं भी आया है वह जब आ जायेगा तो उसके आने के बाद उस डिसीशन को रिवाइज़ करेंगे और वह जो रूपया ज़मीन के लिए दिया है वापिस करेंगे। इसके अलावा 20 लाख रूपया और इस मैमोरियल के लिए क्या सरकार देखी जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने कहा है और अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री के. के. शाह : अभी मेरी आपसे प्रार्थना है कि जैसे आप का सवाल मैंने गौर से सुना उसी तरह आप भी मेरा जबाब सुन लीजिये।

मेरी पहली विनती तो यह है कि दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन हजारों चीज़ों में रेजोल्युशंस पास करके उन की सरकार से सिफारिश करता है तो इस में उन निगाशिगंशस के चलते क्यों नहीं तब उस तरह की सिफारिश उस ने की। ज़मीन की क़िमत लेने की बात तो नहीं थी बल्कि 16 लाख 35 हजार रूपया वह उस पुराने स्ट्रक्चर्स को वहां से गिराने और उस लैंड के बराबर दूसरी जगह कोतवाली बनाने के लिए वह उन दोनों ने एग्रीमेंट किया था। जहां तक गालिब मैमोरियल को सरकार द्वारा पैसे का अनुदान दिये जाने जाने का मामला है तो उस के लिए प्रस्ताव किया गया था और उसे एजुकेशन मिनिस्टरी के पास भेजा गया था और तब एजुकेशम मिनिस्टरी ने उस के लिए पैसा दिया था। इस में भी एजुकेशन मिनिस्टरी को लिखा जायगा। मैंने भी आप से जैसे कहा कि मुझे आप खत की कौपी मिले या फिर एजुकेशन मिनिस्टरी से होम मिनिस्टरी से मिले तो इस बारे में जो भी संभव कार्यवाही हो सकती है वह मैं अवश्य करूंगा।

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या वह रिवाइज़ करेंगे इस चीज को इस बात का तो मंत्री महोदय से साफ़ जबाब ही नही दिया है। मंत्री महोदय से मेरे सवाल का साफ़ साफ़ जबाब दिलवाया जाय।

12.25 hrs.

RE : ERECTION OF STATUE OF MAHATMA GANDHI AT INDIA GATE

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : It had been decided earlier to erect a statue of Mahatma Gandhi at India Gate. But we understand this Govenmrnt has decided to shift the site of Gandhiji's statue from there. We think this is most objectionable. The matter should be discussed by us,

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapura) : We would like to have a statement from the Minister.

श्री रबिराय (पुरी) : हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में बयान दे। यह एक वाक़ई महत्वपूर्ण सवाल है।

SHRI RANGA (Srikakulam) : This is a very important matter. We should consider it (*Interruption*).

SOME HON. MEMBER *rose*—

MR. SPEAKER : There is already a call attention notice on the subject. I have admitted it.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE (Ratnagiri) : May I request you to ask the Government to come well-prepared to answer questions and not say that they require

[Shrimati Sharda Mukherjee]

time, it is under consideration and so on and so forth ?

MR. SPEAKER: There is enough time.

12.26 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

REPORT OF INQUIRY INTO FATAL ACCIDENT AT RAIGUDDA AMB AND BATACHO BAND AND ANNUAL REPORT OF CENTRAL COAL MINES RESCUE STATIONS COMMITTEE, DHANBAD

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : मैं पुनरीक्षित कार्य-सूची में दिये नम्बर 3 के पत्र सभापटल पर रखता हूँ :

(1) 21 मई, 1969 को रायगुड्डा अम्ब और बोटाचो बांध (ननोरा) लोह मैंगनीज खान, मैसूर, की घातक दुर्घटना के जांच प्रतिवेदन की एक प्रति । [*Placed in Library. See* No. LT—2118/69.]

(2) केन्द्रीय कोयला खान रक्षा केन्द्र समिति, धनबाद, के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । [*Placed in Library. See* No. LT2119/69].

BIHAR SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) ACT

THE DEPUTY MINISTR IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI D ERING) : On behalf of Shri Annasahib Shinde, I beg to lay on the Table a copy of the Bihar Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1969 (Hindi and English versions) (President's Act No. 8 of 1969) published in Gazette of India dated the 31st August 1969, under sub-section (3) of section 3 of the Bihar State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1969. [*Placed in Library. See* No. LT-2120/69.]

12.27 hrs

STATEMENT OG BIRLA COTTON MILLS STRIKE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : According to the information furnished by the Delhi Administration, the workers of Birla Cotton Spinning and Weaving Mills Delhi, are on strike from the 26th October, 1969, The management is reported to have offered 4% bonus in terms of the Payment of Bonus Act, 1965. The workers are, however, demanding higher bonus. The matter falls in the State sphere. The Delhi Administration invited the representatives of the management and the workers to bring about an amicable, settlement. These discussions, however, did not succeed. A suggestion was made for reference of the dispute to arbitration. This was not acceptable to the workers. In the circumstances, the Delhi Administration have referred the dispute to the Additional Industrial Tribunal, on the 5th November, 1969 for adjudication. They have simultaneously issued an order prohibiting the strike. The strike, however, continues. The textile workers in other mills expressed their sympathy with the striking workers of the Birla Cotton Spinning and Weaving Mills by going on a day's token strike on the 20th November, 1969.

2. The dispute has already been referred to adjudication; even so, it is open to the parties to come to an agreement after further mutual discussions. The good offices of the Delhi Administration and the Labour Ministry would continue to be available for the purpose. Government expect that the parties would resume negotiations with a view to early settlement